



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249105
CG-DL-E-03102023-249105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945

No. 240]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: एडी (ओआई) - 22/2023

विषय : चीन जन. गण. में मूलतः उत्पन्न या वहां से निर्यात होने वाले "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू)" के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/23/2023-डीजीटीआर.—1. मेसर्स कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदक' के रूप में संदर्भित) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू)" (इसके बाद 'संबंधित वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि सम्बंधित देश से उत्पन्न या वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति का खतरा हो रहा है और उसने सम्बंधित देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन" ("टीपीयू") है। टीपीयू एक पिघल-प्रक्रिया योग्य थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेर है जिसमें प्लास्टिक और रबर के अद्वितीय गुण होते हैं, जिसमें लोच, पारदर्शिता और तेल, ग्रीज़ और घर्षण का प्रतिरोध शामिल है। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेर है जिसमें रैखिक खंडित ब्लॉक कॉपोलीमर होता है जो कठोर और नरम खंडों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद में टीपीयू जोकि पाउडर, ग्रैन्यूल्स, छर्रों, असंशोधित या रंगों, भराव या अन्य एडिटिक्स द्वारा संशोधित रूप में हो सकता है, शामिल है।
4. टीपीयू एक अद्वितीय प्रकार का प्लास्टिक है जो रबर और प्लास्टिक के बीच की खाई को पाटता है। टीपीयू एक तरफ रबर और दूसरी तरफ थर्मोप्लास्टिक सामग्री को चिह्नित करने वाली कई शक्तियों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए टीपीयू को तन्यता और संपीडित भार के तहत विकृत किया जा सकता है। लेकिन बाद में अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसके अलावा, इसे गर्म होने पर खींचा जा सकता है, और जब गर्म भी किया जाता है, तो उन्हें बार-बार पिघलाया और ढाला जा सकता है। टीपीयू की बहुमुखी प्रतिभा की कुंजी यह है कि इसकी कठोरता को अत्यधिक अनुकूलित किया जा सकता है। टीपीयू रबर की तरह नरम या कठोर प्लास्टिक की तरह कठोर हो सकता है। टीपीयू पकड़ प्रदान करने के लिए पारदर्शी या रंगीन या कठोर या नरम / चिकना हो सकता है।
5. टीपीयू पॉलीओल्स (पॉलिएस्टर या पॉलीथर या पॉलीकैप्रोलैक्टोन आधारित या इनमें से एक संयोजन), डायसोसाइनेट्स और शॉर्ट-चेन डायोल्स की प्रतिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए इनमें एडिटिक्स जोड़े जा सकते हैं। सभी तत्वों के संयोजन से कठोरता और यांत्रिक गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है। विचाराधीन उत्पाद आवेदक द्वारा विभिन्न ग्रेड में पेश किया जाता है। हालांकि ये अलग-अलग ग्रेड केवल गुणों के संदर्भ में भिन्न हैं। जिन्हें प्रक्रिया मापदंडों पर नियंत्रण और विशिष्ट एडिटिक्स के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी ग्रेड एक वस्तु के रूप में समान रहते हैं।
6. उत्पाद के दायरे में पॉलिएस्टर-आधारित टीपीयू के साथ-साथ पॉलीथर-आधारित टीपीयू शामिल हैं और पॉलीकैप्रोलैक्टोन-आधारित टीपीयू को विशेष रूप से उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
7. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मोटर वाहन उपकरण पैनलों, कृषि (पशु आईडी टैग), कास्टर पहियों, बिजली उपकरण, खेल के सामान, चिकित्सा उपकरणों, ट्यूब व नली, बेल्ट और प्रोफाइल उद्योग, फुटबियर, इनफ्लेटेबल राफ्ट, एक्सट्रूडेड फिल्म, शीट और प्रोफाइल अनुप्रयोगों की विविधता, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाहरी मामलों, लैपटॉप के लिए कीबोर्ड रक्षक आदि सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। टीपीयू, प्रीमियम मोटरसाइकिल के साथ-साथ यात्री कार बाजार के अंदरूनी हिस्से में रबर और पीवीसी (पोलिविनिल क्लोराइड) का स्थान ले रहा है।
8. जांच अधिनियम का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के कस्टम टैरिफ शीर्षक 39095000 के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि, यह संभव है कि विषय वस्तुओं को अन्य शीर्षकों के तहत भी आयात किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. वर्तमान जांच के पक्ष प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर, पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और पीसीएन, यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि जिन वस्तुओं को भारत में पाटित करने का आरोप लगाया गया है वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्यों और दो उत्पादों के अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं हैं। प्राधिकारी ने नोट किया कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबन्धित देश से आयात की जा रही विषय वस्तुओं के लिए "समान वस्तु" के रूप में माना गया है।

ग. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 है। क्षति की जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022 और पीओआई शामिल हैं।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

13. आवेदन कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि यह भारत में विषय वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है जो भारतीय उत्पादन का 100% है और इसलिए वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए आवश्यक आधार है।
14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार इसने चीन जन. गण. में संबंधित उत्पादक / निर्यातक से विषय वस्तु को आयात किया है। इस तरह के आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी उचित जांच के बाद नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के प्रावधानों के संदर्भ में मात्रा घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में मानदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**सामान्य मूल्य**

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (i) और एडी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, केवल तभी जब जवाब देने वाले चीनी उत्पादक प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और उचित तुलना की अनुमति देती है। एडीडी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 तक, ऐसा न करने पर चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
16. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या मूल्य से संबंधित डेटा या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्माण उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार विषय वस्तुओं के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत

17. वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर संबंधित वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना की गई है। एक्स-फैक्टरी स्तर पर कीमतों को बनाने के लिए उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्टरी स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में सबूत प्रस्तुत किए हैं जिसमें उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित किए गए आयात की मात्रा में वृद्धि, मूल्य में कमी, मूल्य कम बिक्री और घरेलू उद्योग पर मूल्य दमन और निराशाजनक प्रभाव शामिल है। आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक मूल्य पर विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर रिटर्न, इन्वेंट्री के संचय और क्षमता उपयोग के संबंध में इसके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से पाटित किए गए आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तु का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और इस तरह के कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरू करता है, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच में एडी नियम, 1995 के नियम 6 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों singh.shivam@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
23. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें।
24. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच के लिए प्रासंगिक अपनी प्रस्तुतियां दे सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित ईमेल पतों adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in और singh.shivam@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए या नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
26. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7 (2) के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता प्रतिक्रिया / प्रस्तुतियों की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।
29. गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकारी द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

30. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त हो जाती है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश संभव नहीं है, और कारणों का एक बयान कि सारांश क्यूं संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
31. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
32. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या अच्छे कारण विवरण के बिना किए गए किसी भी निवेदन को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
33. इच्छुक पक्ष प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

34. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

35. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसा कि उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, 29th September, 2023

INITIATION NOTIFICATION

Case No. AD(OI)–22/2023

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “**Thermoplastic Polyurethane (TPU)**” originating in or exported from **China PR**

F. No. 6/23/2023-DGTR.—1. Covestro (India) Pvt Ltd. (hereinafter also referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred to as “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as “Rules”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “**Thermoplastic Polyurethane**” (“**TPU**”) (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from **China PR** (hereinafter referred to as “subject country”).

2. The applicant has alleged that injury and threat of injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is “**Thermoplastic Polyurethane**” (“**TPU**”) originating in or exported from China PR. TPU is a melt-processable thermoplastic elastomer having unique properties of plastic and rubber, including elasticity, transparency, and resistance to oil, grease, and abrasion. TPU is thermoplastic elastomer consisting of linear segmented block copolymer composed of hard and soft segments. PUC covers TPU in the form of powder, granules, pellets, unmodified or modified by colourants, fillers or other additives.
4. TPU is a unique type of plastic that bridges the gap between rubber and plastic. TPU combines a multitude of strengths characterizing rubber on one hand and thermoplastic materials on the other. TPU can, for instance, be deformed under tensile and compressive load, but afterwards return to their original shape. Furthermore, it can be stretched when heated, and when heated even, they can be melted and moulded over and over again. The key to TPU's versatility is that its hardness can be highly customized. TPU can be as soft as rubber or as hard as rigid plastic. TPU can be transparent or coloured or hard or soft/smooth to provide grip.
5. TPU is obtained from the reaction of polyols (polyester or polyether or polycaprolactone based or a combination of these), diisocyanates and short-chain diols. Additives can be added to these to achieve special properties. By combining all the elements, a wide range of hardness and mechanical properties can be achieved. PUC is offered by the applicant in different grades. However, these different grades are different merely in terms of properties, which can be achieved through control on process parameters and use of specific additives. All these grades remain the same as one article.
6. The product scope covers polyester-based TPU as well as polyether-based TPU, and polycaprolactone-based TPU is specifically excluded from the scope of product.
7. The product under consideration is used in a wide variety of applications including automotive instrument panels, agriculture (animal ID tags), caster wheels, power tools, sporting goods, medical devices, tubes & hoses, belts and profiles industry, footwear, inflatable rafts, variety of extruded film, sheet and profile applications, outer cases of mobile electronic devices, keyboard protectors for laptops etc. TPU is also substituting rubber and PVC (Poly Vinyl Chloride) in premium motorcycle market as well as passenger car interiors.
8. The product under investigation is being imported under Custom Tariff Heading 39095000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on scope of the product.
9. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority.

B. LIKE ARTICLE

10. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the applicant in India are being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

11. The subject country in the present petition is China PR.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

12. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April, 2022 to 31st March, 2023. The injury investigation period covers the periods 1st April, 2019 – 31st March, 2020, 1st April, 2020 – 31st March, 2021, 1st April, 2021 – 31st March, 2022 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

13. The application has been filed by Covestro (India) Pvt Ltd. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India constituting 100% of the Indian production and therefore, has the requisite standing to file the present application.
14. As per the information submitted by the applicant, it has imported the subject goods from related producer/exporter in China PR. Considering the volume of such imports is not significant, the Authority notes, after due examination, that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of the provisions of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**Normal Value**

15. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure-I to the Anti-Dumping Duty Rules, the normal value for Chinese producers may be determined based

on the cost or domestic selling price prevailing in China PR, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the Anti-Dumping Duty Rules, failing which, normal value for the Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.

16. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available. The normal value has been, thereby, constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

Export Price

17. The export price for the subject goods has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI & S) transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

Dumping Margin

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

19. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to the production or consumption in India, price undercutting, price underselling and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of sale, profitability, return on investment, accumulation of inventories and capacity utilization as a result of increase in imports of product under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. The principles as stipulated under Rule 6 of the said Rules shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in and singh.shivam@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
23. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

K. TIME LIMIT

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in and singh.shivam@gov.in

within thirty (30) days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

27. Any party making any confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
28. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

34. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

35. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority